



JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur- 302 004

GRAND AUCTION

Of Group Housing & Commercial Plots

S. No.	Details of Plots	Zone	Area (sq.mtr.)	F.A.R.	Height	Max. Coverage Area	Bid start Price (Rs. per sq. mtr.)	Earnest Money (In Rs.)	Date & Time of Auction
1.	Group Housing Plots in Gokul Nagar Scheme (Gokulpura) Kalwar Road, Jaipur GH-1 GH-2	16	5283.37 5060.91	Max. 2.25	As per Building Bye laws Point No. 8.11	35%	25,000/-	30 Lac each	14.08.14 02:30 P.M.
2.	Commercial Plots in Gokul Nagar Scheme (Gokulpura) Kalwar Road, Jaipur C-4 C-5	16	2436.63 2451.86	Max. 2.25	As per Building Bye laws Point No. 8.11	Within Set Back	40,000/-	30 Lac each	20.08.14 02:30 P.M.
3.	Commercial Plot Near Kuber Complex, Opposite Police H.Q. Lalkothi Scheme	3	836.10	Max. 2.25	15 Mtr.	Within Set Back	95,000/-	30 Lac	21.08.14 02:30 P.M.
4.	Group Housing Plots in Shiv Enclave JDA Scheme, Village- Ganpatpura, Teh.- Sanganer, Jaipur G-4 (Corner) G-7 (Corner)	8	5003.73 5210.91	Max. 2.25	As per Building Bye laws Point No. 8.11	35%	20,000/-	30 Lac each	26.08.14 02:30 P.M.
5.	<u>Group Housing Plots in Shiv Vihar Scheme, Village- Mangawas, Teh.-Sanganer, Jaipur</u> <u>GH-2</u> <u>GH-3</u>	18	<u>5862.82</u> 5875.08	Max. 2.25	27 Mtr. + Stilt.	40%	18,000/-	<u>30 Lac each</u>	27.08.14 02:30 P.M.
6.	Group Housing Plot No. G-2 in Village- Siroli, Jaipur	9	8015.51	Standard 1.33	27 Mtr.	35%	12,000/-	30 Lac	28.08.14 02:30 P.M.

Auction Place - JDA Auction Hall

For Further details & conditions of auction please log on to our website www.jaipurjda.org or contact

Addl. Director (Revenue & Property Disposal): Phone No.: 0141-2569696 (Ext.-7107, 7021, 1119, 1128)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बड़ी सम्पत्ति की नीलामी की शर्तें :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को रु. 5,000/- बतौर रजिस्ट्रेशन मनी जमा कराने होंगे। उक्त जमा रजिस्ट्रेशन राशि किसी भी बोलीदाता को वापिस नहीं की जावेगी। इसके अतिरिक्त राशि रु. 50 लाख अमानता राशि बतौर सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम बोली शुरू होने से पूर्व जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता के नाम से बोली छूटने पर जमा अमानता राशि भूखण्ड की कीमत में समायोजित करली जावेगी तथा अन्य व्यक्तियों की अमानता राशि मौके पर ही वापिस लौटा दी जावेगी। बोली प्रारम्भ होने पर नीलामी समिति अपने सर्व सम्मत निर्णय से किसी अन्य बोलीदाता को पंजीयन कराने/बोली में भाग लेने की अनुमति दे सकती है।
2. नाबालिग अथवा नाबालिग के नाम से किसी बोलीदाता को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा।
3. यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिस व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी बोलीदाता के नाम उच्चतम बोली छुटती है, कब्जा पत्र/लीज डीड उसी के नाम जारी किया जावेगा।
4. 1 वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी की राशि नजराना राशि के साथ ही देय होगी जो कि कब्जा पत्र जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी।
5. राज्य सरकार के निर्देशानुसार 300 व.मी. से बड़े आवासीय भूखण्डों एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर 10/- रु. प्रति व.मी. एवं व्यावसायिक भूखण्डों पर 25/- रु. प्रति व.मी. की दर से BSUP Shelter Fund Charges देय होंगे।
6. भूखण्ड की न्यूनतम बोली रु. प्र.व.मी. से प्रारम्भ होगी। जयपुर विकास आयुक्त को बिना कारण बताये उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. नीलामी के समय यदि नीलामी समिति को ऐसा अनुभव हो कि बोली की दर उचित प्राप्त नहीं हो रही है अथवा नीलामी ठीक ढंग से नहीं चल रही है तो मौके पर ही बोली को अस्वीकार कर नीलामी को स्थगित किया जा सकता है।
8. (अ)सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूखण्ड की बोली का 10 प्रतिशत राशि बोली की स्वीकृति के 72 घण्टे में जमा करानी होगी अन्यथा अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी। क्रेता को शेष राशि अर्थात् 90 प्रतिशत राशि नीलामी की पुष्टि पत्र (मांग पत्र) जारी करने की 30 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी।
(ख)यदि क्रेता उपरोक्त सं. 8(अ) के अनुसार राशि अदा नहीं कराना चाहता है तो निम्नलिखित शर्तें के अनुसार राशि जमा कराने का विकल्प बोली छूटने के 72 घण्टे में दे सकता है :-
इसके अन्तर्गत कुल कीमत की 25 प्रतिशत बोली छूटने अथवा मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराकर, बकाया 75 प्रतिशत राशि 4 तिमाही किश्तों द्वारा 15 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कर सकता है ब्याज त्रैमासिक किश्तें घटती हुई बकाया पर तिमाही देय होगा। लीजडीड सभी चार किश्तों के भुगतान के पश्चात् उसी स्थिति में दिया जावेगा जबकि सम्पूर्ण कीमत जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो जावेगी।
(स)यदि क्रेता किसी किश्त को निर्धारित समय पर जमा नहीं करता है तो विशेष मामलों में आयुक्त जबिप्रा एक किश्त की भुगतान को एक तिमाही विलम्ब से जमा करने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं परन्तु इस अवधि का ब्याज 22.5% वार्षिक की दर से लिया जावेगा। और यदि क्रेता इस प्रकार भुगतान नहीं करता है तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी और प्राधिकरण पुनः उक्त भूखण्ड का कब्जा मय उस पर निर्मित सम्पत्ति के प्राप्त कर लेगा, और डिफाल्टर किसी प्रकार का कम्पनशेशन पाने का अधिकारी नहीं होगा।
(द)जो भूखण्ड संस्थाओं को आवंटित किये जावेगे और जिनका मूल्य रुपये एक करोड़ या इससे अधिक होगा, वह भी उपरोक्त भुगतान की विधि अपना सकेगे।
(य)उपरोक्त (अ) के अनुसार पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राधिकरण 15 दिवस में भूखण्ड का कब्जा सम्भाल देगा।

9. भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीजहोल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। आवासीय एवं संस्थानिक भूखण्डों के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्डों पर लीज 5 प्रतिशत की दर से प्रचलित आवासीय आरक्षित दर पर देय होगी, जो कि प्रथम पंच वर्ष तक आधी दर से देय होगी तथा 5 वर्ष के पश्चात पूरी शहरी जमाबन्दी वसूल की जावेगी (यह राशि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व अग्रिम जमा करानी होगी) शहरी जमाबन्दी की एक मुश्त राशि जो कि पूर्ण दर पर राशि की 8 गुणा होती है, को भी जमा कराये जाने का प्रावधान है।
10. क्रेता को भूखण्ड "जहाँ है जैसा है" के आधार पर हस्तान्तरित होगा।
11. नीलामी में क्रय किये गये भूखण्ड के भवन मानचित्र भवन निर्माण प्रारम्भ कराने से पहले अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है। भवन निर्माता को इस सन्दर्भ में एक शपथ पत्र देना होगा कि वह प्राधिकरण के भवन विनियम की पालना करेगा। भवन निर्माण नियमों की अवहेलना पर नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जावेगी। क्रेता को भूमि क्रय के 2 वर्ष में अथवा कम्प्लीशन सर्टिफिकेशन जारी करने से पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। अल्सर एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत नियमानुसार सक्षम अधिकारी से भवन निर्माण से पूर्व स्वीकृति लेने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
12. योजना के लिए प्रचलित भवन निर्माण विनियम एवं समय-समय पर संशोधित विनियमों में दिये गये बायलॉज के अनुसार तथा स्थल मानचित्र में दी गयी बिल्डिंग लाईनस् के अनुसार भवन निर्माण करना होगा। मुख्य पैरामीटर्स निम्नानुसार होंगे :-
 - (i) अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल
 - (ii) अधिकतम ऊँचाई
 - (iii) एफ.ए.आर.
13. आवश्यकता होने पर नीलामी को अगले दिन भी निरन्तर जारी रखा जा सकता है।
14. राजस्थान सुधार (नगरीय भूमि का निर्वहन) नियम 1974 के नियम 14(क) उप नियम 1 के अनुसार :- यदि किसी व्यक्ति ने, जो आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लोक नीलामी के माध्यम से भूमि क्रय करता है, उस तारीख से जिसको भूमि का कब्जा सौंप दिया जाता है :-
 - (i) 1000 वर्गमीटर तक के आकार के भू-खण्ड की दशा में 3 वर्ष या
 - (ii) 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 5000 वर्गमीटर तक के आकार के भू-खण्ड की दशा में 5 वर्ष या
 - (iii) 5000 वर्गमीटर से अधिक के आकार के भू-खण्ड दशा में 7 वर्ष या के भीतर भवन का सन्निर्माण नहीं किया है तो वह तीन वर्ष तक संबंधित न्यास को वर्तमान विद्यमान आरक्षित कीमत के एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उद्ग्रहण का संदाय करेगा और यदि भवन का अब तक भी सन्निर्माण नहीं किया गया है तो भूमि का पट्टा रद्द हो जायेगा।
15. क्रेता द्वारा राज्य सरकार/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों, निर्देशों, आदेशों एवं निर्णयों की अनुपालना की जावेगी।
16. आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के अनुसार 50 लाख या 50 लाख से अधिक सम्पत्ति का मूल्य होने पर नियमानुसार सम्पत्ति मूल्य का एक प्रतिशत टी.डी.एस. की राशि राजकीय कोष में जमा कराने की जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की है। इसकी सूचना क्रेता द्वारा नीलामी प्रकोष्ठ को दिया जाना आवश्यक है।
17. नीलामी के विज्ञापन में दी गई शर्तें उक्त शर्तों का ही हिस्सा मानी जावेगी।
उपरोक्त सभी शर्तें नीलामी से पूर्व मैंने/हमने सुन ली है/पढ़ ली है/देख ली है तथा समझ ली है और मैं/हम इन सभी शर्तों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं।

क्रेता के हस्ताक्षर

भूखण्ड सं. क्षेत्रफल व.मी. योजना दर

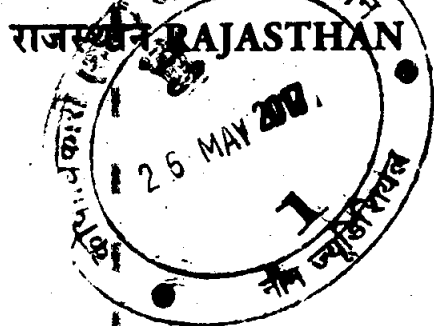
रु. प्रति वर्गमीटर, नीलामी तिथि दिनांक नाम क्रेता

..... पिता का नाम पता

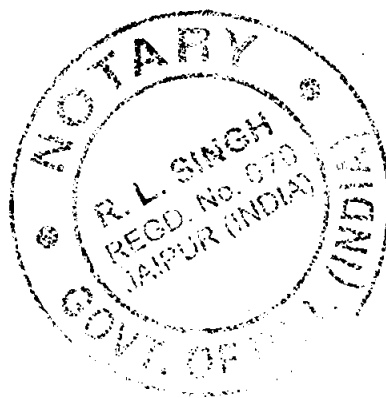
.....

विशेषाधिकारी (संसाधन विकास)

क्रेता के हस्ताक्षर



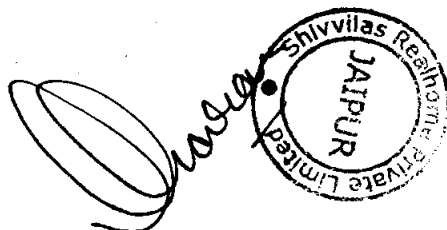
G 576185



शपथ-पत्र

मैं चरण सिंह खंगारोत, आयु 39 वर्ष, पुत्र श्री मुकुट सिंह खंगारोत, बहैसियत अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता मैसर्स शिवविलास रियलहोम प्रा० लि०, पंजीकृत पता-प्लॉट नम्बर 8, हर्ष
दावर, त्रिवेणी नगर मोड़, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, सशपथ पूर्वक बयान करता हूँ :-

1. यह कि हमारी फर्म ने ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-2, शिव विहार योजना,
ग्राम-मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा
दिनांक 27.08.2014 को सम्पादित नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर क्रय किया है।



ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (INDIA)

16-09-17

27 11 2017

क्रमांक सख्या 100 दिनांक

मुद्रांक का मूल्य

क्रता का नाम Shiv Vilas Realhome Pvt. Ltd.

पति/पति

निवास 8, Tivari Nagar, Jaipur

कार्य का: Affidavit/undertaking/Declaration

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत

स्टाम्प का नं. 100 दिनांक 27/11/2017

1. शासक

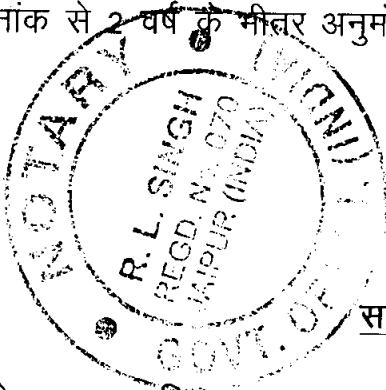
2. न्याय

दस्तावेज नं. 100 दिनांक 27/11/2017

✓
शिव विलास
स्टाम्प विक्रेता
सफ्ट नं. 3, मालवीय नगर
जयपुर

2. यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.12.2014 को उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख भी शपथकर्ता फर्म के नाम जारी कर दिया गया है।
3. यह कि नीलामी की शर्तों के बिन्दु संख्या 11 में यह स्पष्ट है कि नीलामी में क्रय किये गये भूखण्ड के भवन मानचित्र भवन निर्माण प्रारम्भ कराने से पहले अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता फर्म द्वारा उक्त भूमि पर भवन का निर्माण भवन विनियमों के अनुसार ही किया जावेगा और भवन विनियमों की पूर्णरूप से पालना की जावेगी।
5. यह कि शपथकर्ता फर्म द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन मानचित्र भूखण्ड के क्रय करने की दिनांक से 2 वर्ष के भीतर अनुमोदित करवा लिये जावेंगे।

जयपुर,
दिनांक:



सत्यापन

हस्ताक्षर शपथगहिता

(चरण सिंह)

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र की मद संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है। इसमें कोई भी तथ्य असत्य व मिथ्या अंकित नहीं किया गया है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

दिनांक:

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (INDIA)

16-09-17

सत्यापनकर्ता
(चरण सिंह)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 20] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 1999 / चैत्र 1, 1921 (शक)
No. 20] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 1999 / CHAITRA 1, 1921 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

New Delhi, the 22nd March, 1999/Chaitra 1, 1921 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 22nd March, 1999, and is hereby published for general information:—

**THE URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) REPEAL
ACT, 1999**

No. 15 OF 1999

[22nd March, 1999.]

An Act to repeal the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

BE it enacted by Parliament in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999.

Short title,
application and
commencement.

(2) It applies in the first instance to the whole of the States of Haryana and Punjab and to all the Union territories; and it shall apply to such other State which adopts this Act by resolution passed in that behalf under clause (2) of article 252 of the Constitution.

(3) It shall be deemed to have come into force in the States of Haryana and Punjab and in all the Union territories on the 11th day of January, 1999 and in any other State which adopts this Act under clause (2) of article 252 of the Constitution on the date of such adoption; and the reference to repeal of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 shall, in relation to any State or Union territory, mean the date on which this Act comes into force in such State or Union territory.

2. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (hereinafter referred to as the principal Act) is hereby repealed.

Repeal of Act
33 of 1976.

Savings.

3. (1) The repeal of the principal Act shall not affect—

(a) the vesting of any vacant land under sub-section (3) of section 10, possession of which has been taken over by the State Government or any person duly authorised by the State Government in this behalf or by the competent authority;

(b) the validity of any order granting exemption under sub-section (1) of section 20 or any action taken thereunder, notwithstanding any judgment of any court to the contrary;

(c) any payment made to the State Government as a condition for granting exemption under sub-section (1) of section 20.

(2) Where—

(a) any land is deemed to have vested in the State Government under sub-section (3) of section 10 of the principal Act but possession of which has not been taken over by the State Government or any person duly authorised by the State Government in this behalf or by the competent authority; and

(b) any amount has been paid by the State Government with respect to such land,

then, such land shall not be restored unless the amount paid, if any, has been refunded to the State Government.

Abatement of legal proceedings.

4. All proceedings relating to any order made or purported to be made under the principal Act pending immediately before the commencement of this Act, before any court, tribunal or other authority shall abate:

Provided that this section shall not apply to the proceedings relating to sections 11, 12, 13 and 14 of the principal Act in so far as such proceedings are relatable to the land, possession of which has been taken over by the State Government or any person duly authorised by the State Government in this behalf or by the competent authority.

Repeal and saving.

5. (1) The Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Ordinance, 1999 is hereby repealed.

Ord. 5 of 199

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

RAGHBIR SINGH,
Secy. to the Govt. of India.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JAIPUR BENCH, JAIPUR**

ORDER

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO.3093/1999

The Rajasthan Chamber of Commerce & Industry having its registered office at Mohan Lal Sukhadia Chamber Bhawan, M.I. Road, Jaipur through its Honorary Secretary General K.L. Jain, son of Late Shri G. Jain, aged about 65 years, resident of SP-5, Bhabha Marg, Tilak Nagar, Jaipur.



Petitioner

versus

1. The State of Rajasthan through its Secretary, Urban Development and Land Ceiling Deptt., Govt. of Rajasthan, Jaipur.

2. The Divisional Commissioner, Government of Rajasthan, Jaipur.

Date of Order: 15.9.2016

HON'BLE MR. JUSTICE VEERENDR SINGH SIRADHANA

Mr. Sameer Jain, for the petitioner.

Mr. Ashish Sharma on behalf of

Mr. Rajendra Prasad, AAG, for the State-respondents.

Aggrieved of the notice dated 1st November, 1993; the petitioner-Company instituted an appeal before the Court of Divisional Commissioner, Jaipur, which was declined by the impugned order dated 17 May, 1999; and therefore, the petitioner has instituted the present writ application, praying for the following relief(s).

“(i) The impugned order passed by the competent authority on 1.11.93 and the order passed by the Divisional Commissioner on 17.5.99 be quashed and set aside:

(ii) An appropriate writ, order or direction be passed directing that the respondents that they shall not take possession of the disputed land which is in possession of the petitioner Chamber; and

(iii) By an appropriate writ, order or direction, the Hon'ble Court may restrain the respondents from taking any further action in the matter under the provisions of ULCAR Act.

Any other appropriate order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the facts and circumstances of the case may also kindly be passed in favour of your humble petitioner Chamber."



Briefly, the essential skeletal material facts necessary for appreciation of the controversy are that the competent authority in exercise of powers under Section 10 of the Urban (Ceiling and Regulation) Act, 1976, (for short, 'the Act of 1976'), made a direction calling upon the petitioner to hand-over the possession of excess land to the Jaipur Development Authority (J.D.A.), within 30 days from the receipt of communication. An appeal instituted under Section 33 of the Act of 1976, along with stay application, was declined vide order dated 17th May, 1999 (Annexure-19).

From the materials available on record and response filed on behalf of the State-respondents, it is reflected that the excess vacant land was and remained in possession of the petitioner. While issuing notice on the writ application, an order of *status quo* was granted by this Court on 17th June, 1999; which has continued, till date.

Learned counsel for the petitioner, while moving an application for early hearing of the case, referred to Notification dated 7th October, 1999; which reads thus:

"URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, October 7, 1999

No.F.22(24)UDD/2/90.- The following resolution which was passed by the Rajasthan State Legislature on 23rd September, 1999 adopting the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999 (Central Act No.15 of 1999) is hereby published for information of general public.

'RESOLUTION

Whereas the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976) enacted by Parliament in pursuance to the provision of Article 252 of the Constitution:-

Whereas the aforesaid Central Act was adopted w.e.f. 9-3-1976 for the State of Rajasthan by a resolution passed by the Rajasthan State Legislature;

Whereas the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976) has been repealed as respect to the States of Haryana and Punjab and all the Union Territories w.e.f. 11th January, 1999 by the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999 (Central Act No. 15 of 1999);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (2) of Article 252 of the Constitution of India this house adopts the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999 (Central Act No. 15 of 1999)."

A glance of the notification as extracted hereinabove, would reveal that the Act of 1976, has been repealed and by a RESOLUTION, the House adopted the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999.

Referring to the opinion of the Supreme Court in the case of **Pt. Madan Swaroop Shrotiya Public Charitable Trust Vs. State of U.P. And Ors.:** AIR 2000 SC 3415, learned counsel urged that the present proceedings have to be abated.

At this juncture, it will be useful to consider the text of para No.3, 4 and 5 of the judgment in the case of **Pt. Madan**



In view of the above, the writ proceedings are hereby abated under Section 4 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999.

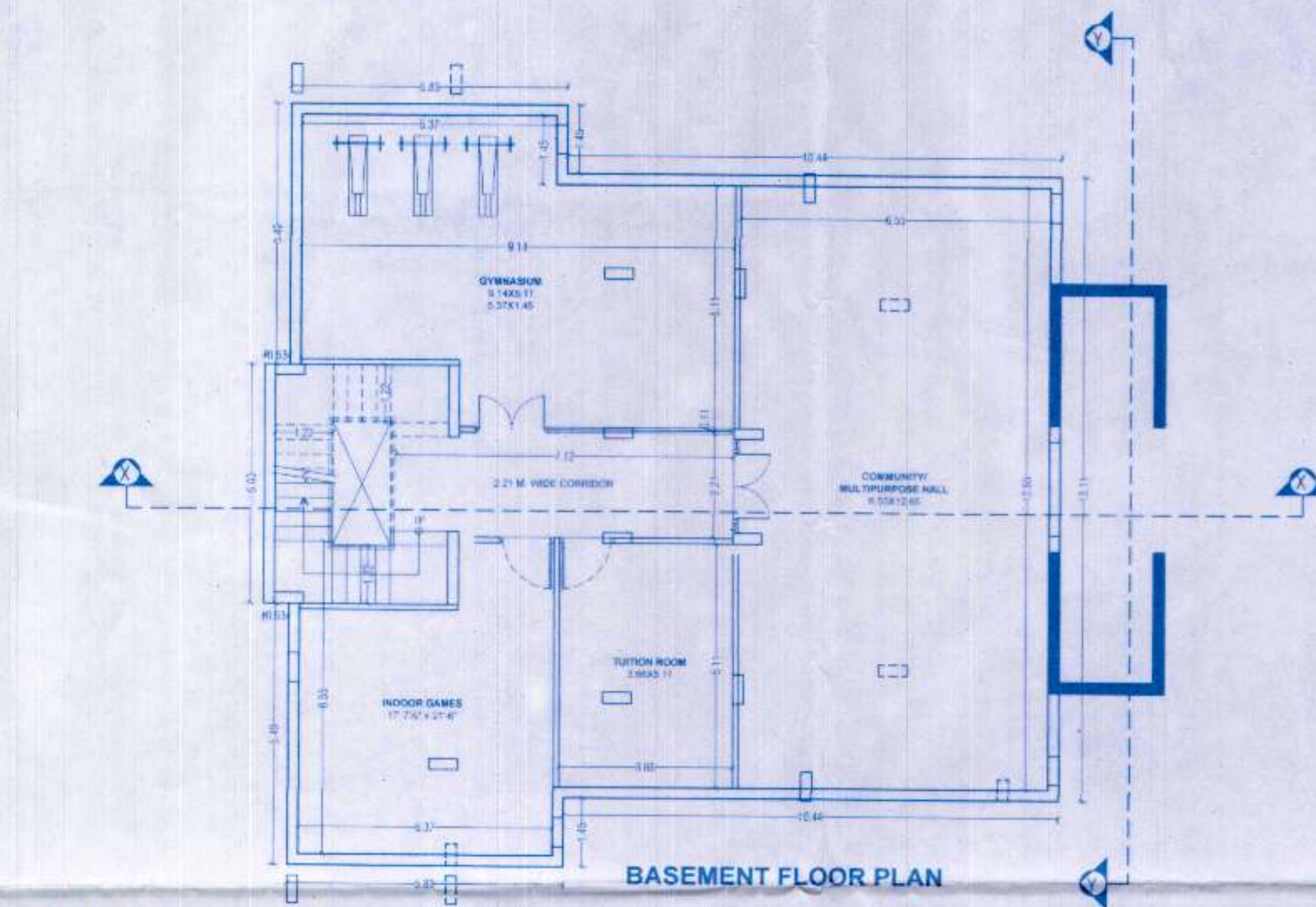
The writ application stands disposed off accordingly.



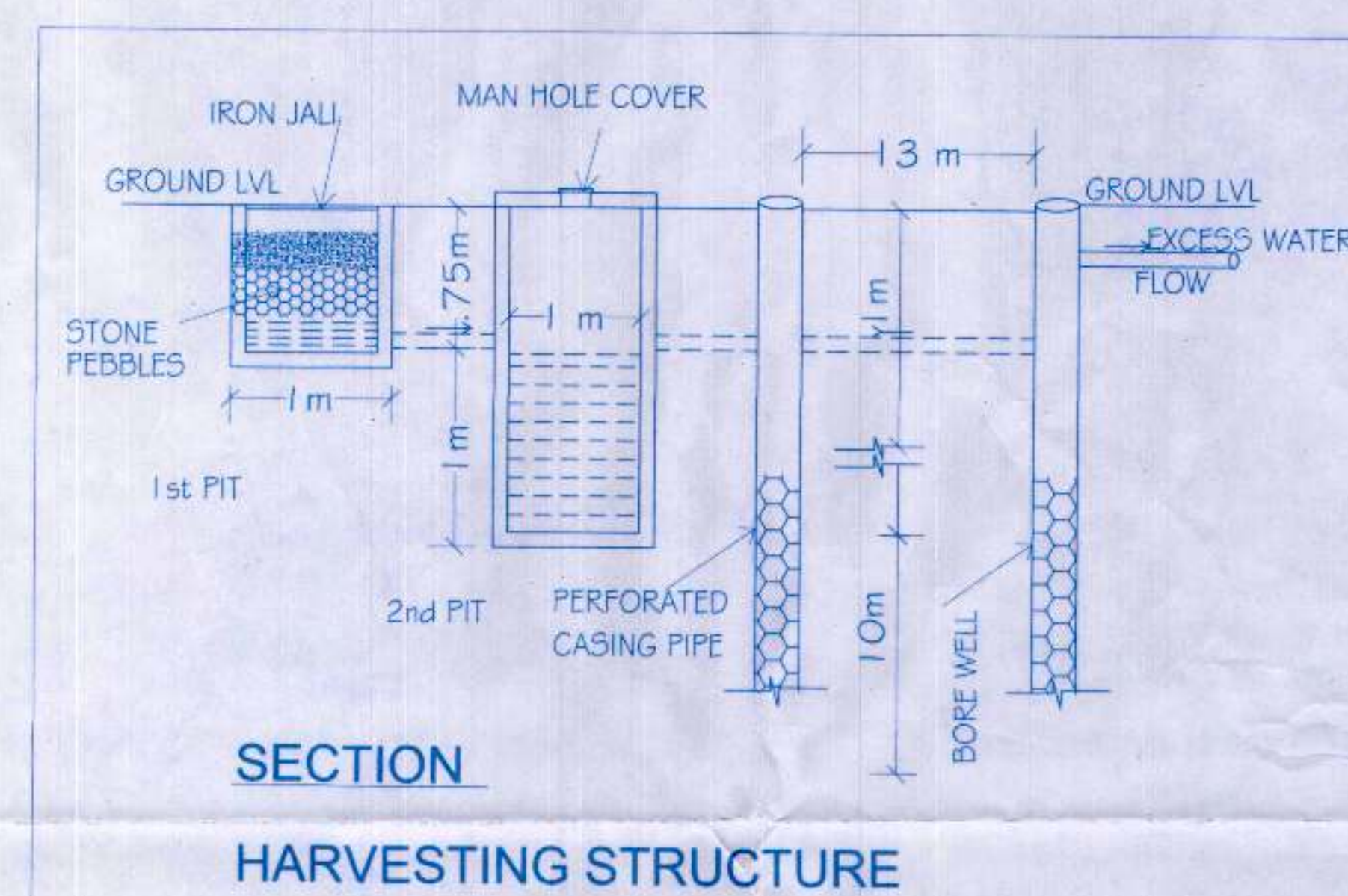
(VEERENDR SINGH SIRADHANA),J.



सत्यमेव जयते



GH-1



SECTION

HARVESTING STRUCTURE

PLOT AREA = 5862.82 SQ.MT.
F.A.R. PERMISSIBLE = $5862.82 \times 2.25 = 13,191.34$ SQ.MT.
F.A.R. ACHIEVED = 13165.97 SQ.MT. (2.245) F.A.R
CLUB HOUSE PERMISSIBLE = $13165.97 \times 0.05 = 658.29$ SQ.MT.
CLUB HOUSE ACHIEVED = 348.51 SQ.MT.
STORE AREA PERMISSIBLE = $13165.97 \times 0.03 = 394.97$ SQ.MT.
STORE AREA ACHIVED = 393.12 SQ.MT.
SERVICES AREA PERMISSIBLE = $13165.97 \times 0.07 = 921.61$ SQ.MT.
SERVICES AREA ACHIEVED = 4.14 SQ.MT.
LANDSCAPING PERMISSIBLE = 586.28 SQ.MT.
LANDSCAPING ACHIEVED = 614.50 SQ.MT. (10.48%)

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING $\frac{\text{FAR ACHIEVED}}{75} = \frac{13165.97}{75} = 175.54$

+ 25% EXTRA VISITOR PARKING = $175.54 \times 1.25 = 219.42 \text{ E.C.U.}$

TOTAL PARKING REQ. = 219.42 E.C.U.

PARKING AVAILABLE =

CAR PARK IN OPEN AREA = 89

CAR PARK IN STILT = 77

TOTAL CAR PARK = 166 E.C.U.

SCOOTER PARK IN OPEN AREA = 67

SCOOTER PARK IN STILT = 96

TOTAL TWO WHEELER = $163 \text{ NO.} \times 54.33 \text{ E.C.U.}$

TOTAL PARKING PROVIDED = $166 + 54.33 = 220.33 \text{ E.C.U.}$

AREA CALCULATION TABLE															
Sr. No.	FLOORS	BLOCK AREA sq. mt.	CUT AREA sq. mt.	GROSS BUILT UP sq. mt.	FIRE ESCAPE STAIRCASE sq. mt.	RAILCOTIN PROJECTION sq. mt.	HARDPOBE (W.R.) sq. mt.	NET BUILT UP sq. mt.	LIFT sq. mt.	STAIR CASE sq. mt.	CORRIDOR sq. mt.	STORE sq. mt.	SERVICES sq. mt.	P. A. E. sq. mt.	CLUB HOUSE sq. mt.
1.	BASEMENT	232.78	—	232.78	—	—	—	232.78	—	18.39	—	—	—	—	232.78
2.	STILT	2062.63	—	2062.63	38.28	—	—	2062.63	29.89	28.35	—	—	—	—	115.73
3.	FIRST	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
4.	SECOND	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
5.	THIRD	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
6.	FOURTH	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
7.	FIFTH	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
8.	SIXTH	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
9.	SEVENTH	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
10.	EIGHT	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
11.	NINTH	2065.18	110.09	1955.09	38.28	106.79	25.83	1784.19	29.89	28.35	222.31	43.68	0.46	1459.50	
12.	TERRACE	71.21	—	71.21	—	—	—	71.21	—	—	—	—	—	—	
13.	TOTAL	20953.24	990.81	19962.43	382.80	961.11	232.47	18424.33	298.90	301.89	2000.79	393.12	4.14	13135.50	348.5

ACHIEVED F.A.R. = 13135.50 SQ.MT.
CORRIDOR AREA PERMISSIBLE = $13135.50 \times 0.15 = 1970.32$ SQ.MT.
ACHIEVED CORRIDOR = 2000.79 SQ.MT.
EXCEED CORRIDOR AREA = $2000.79 - 1970.32 = 30.47$ SQ.MT.
TOTAL NET ACHIEVED F.A.R. = $13135.50 + 30.47 = 13165.97$ SQ.MT.

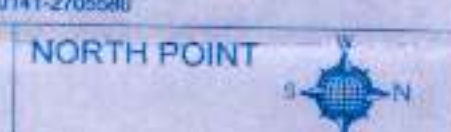
DRAWING TITLE

**SITE - PLAN & CALCULATION TABLE /
BASEMENT FLOOR PLAN**

PROJECT TITLE:-
PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. GH-2 OF
"SHIV VIHAR" YOJANA AT VILLAGE - MANGAYWAS AT TEHSIL
SANGANER, JAIPUR IN PRIME MINISTER YOJANA-2015



SCALE 1:100



For SHIVILAS REALHOME PVT. LTD.

Director/Act. Signatory


 GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
 Architect
 CW 197/22030

OWNER

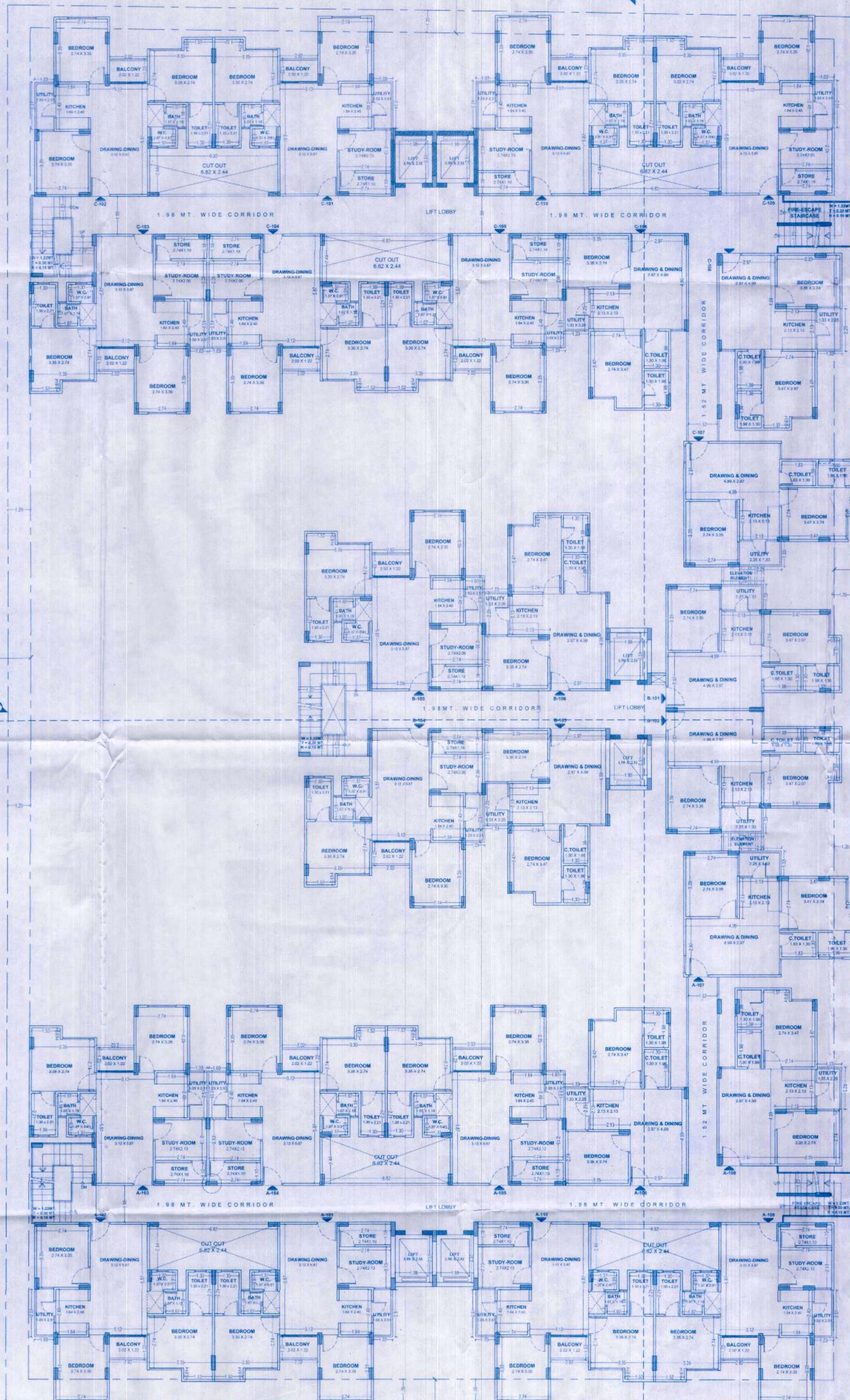
ARCHITECT



GYANENDRA SINGH SNEKHAR
Architect
CG/97/22030

OWNER

ARCHITEC



FIRST FLOOR PLAN

R O A D 18.00 MT. W I D E

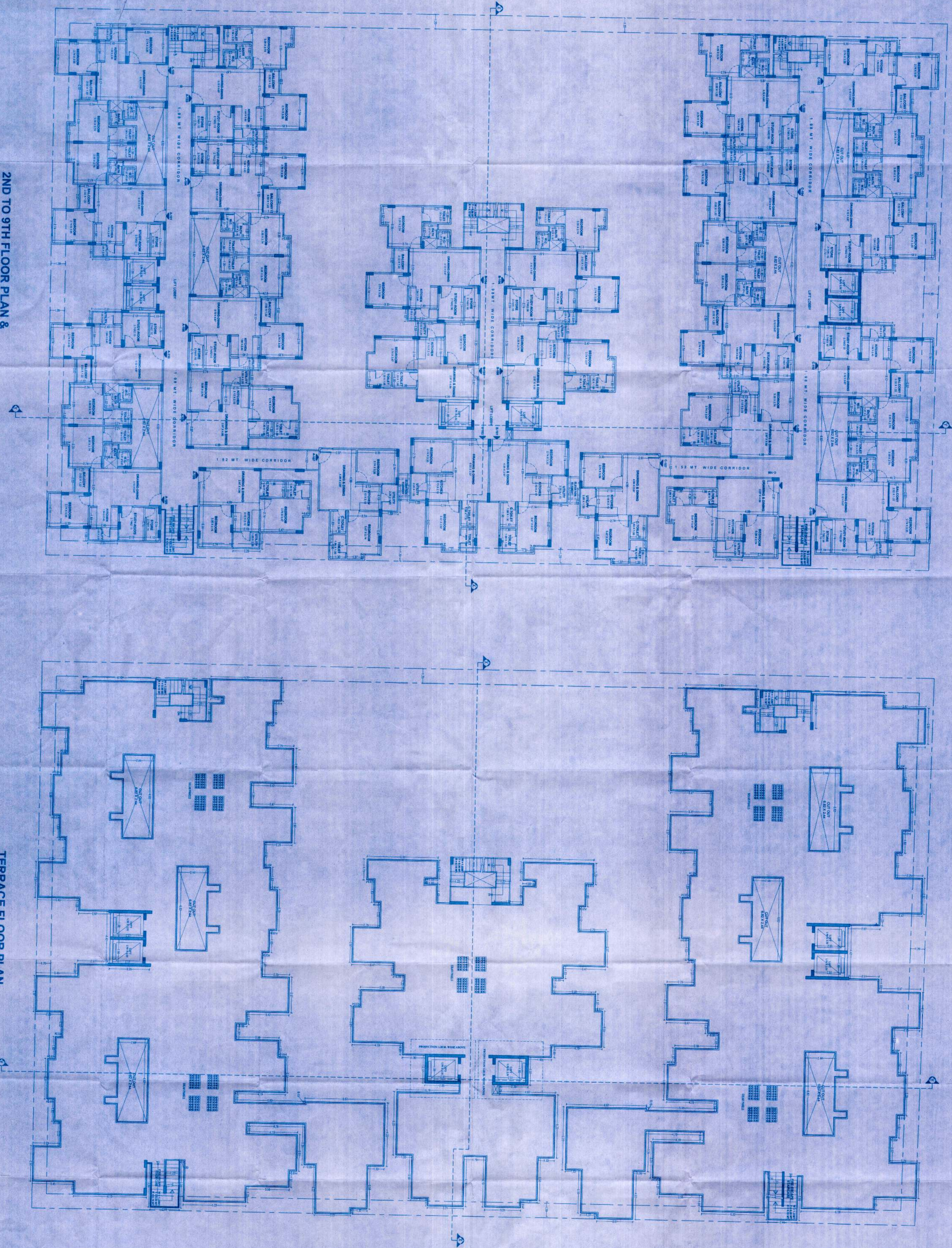
DRAWING TITLE
FIRST FLOOR PLAN
PROJECT TITLE -
PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. GH-3 OF
"SHIV VIHAR" VILLAGE - MANGAYWAS AT TEHSIL
SANGANER, JAIPUR IN PRIME MINISTER YUJANA-2015

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705080

SCALE 1:100 NORTH POINT

For ARCHITECTURE REAL HOME EDC LTD.
Design/Author/Signatory
STANDARDIZATION COMMITTEE
APR 2015
CA/6722030

OWNER ARCHITECT



2ND TO 9TH FLOOR PLAN &

TERRACE FLOOR PLAN

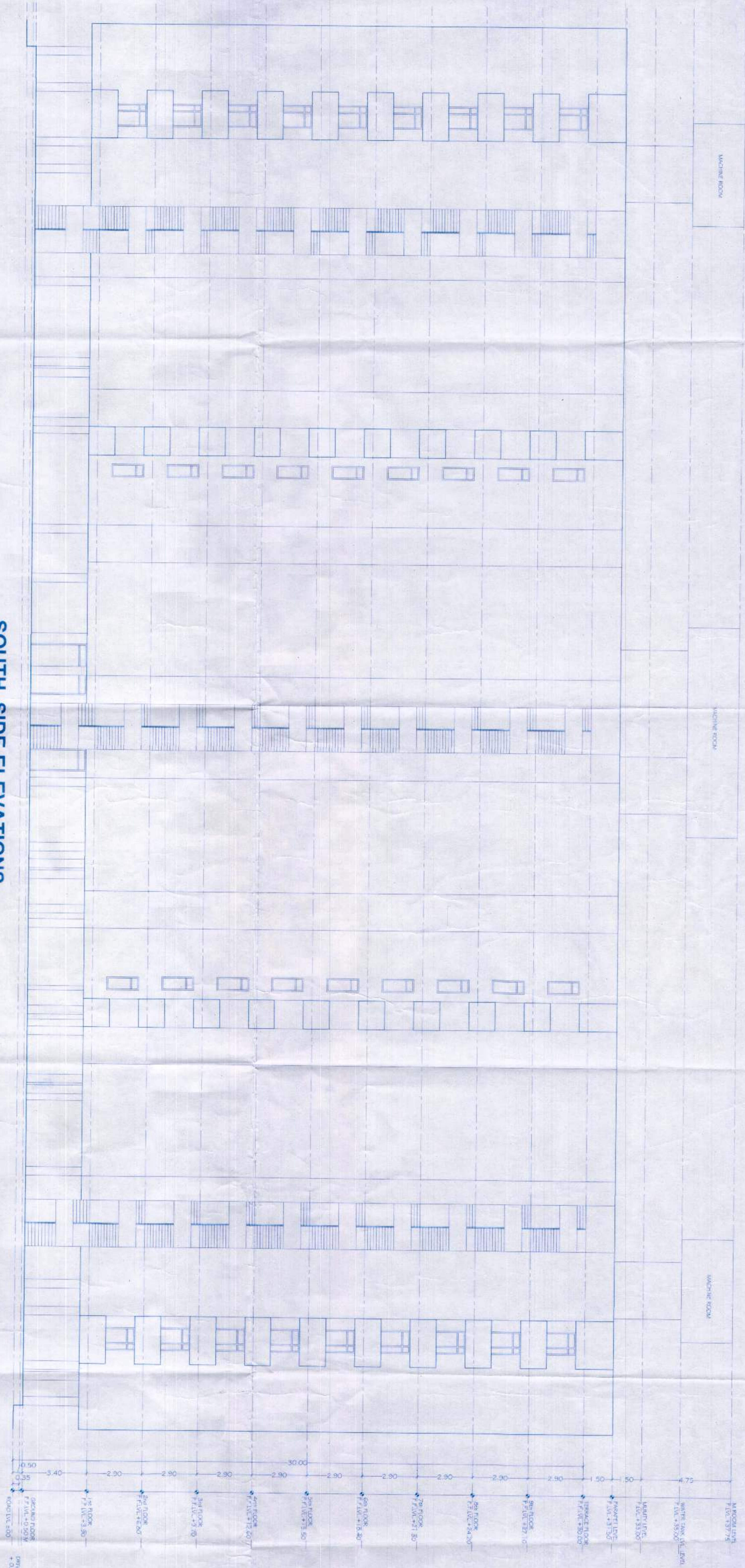
DRAWING TITLE
2ND TO 9TH FLOOR PLAN &
TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE
PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. CH-2 OF
SHIV VIHAR - YOGAM AT VILLAGE - MANGRAWAS AT THERL
SANGAREN, JAPUR IN PRIME MINISTER YOGAM-2015

ideas
ARCHITECTURE & INTERIORS
PLOT NO. CH-2 OF SHIV VIHAR - YOGAM AT VILLAGE - MANGRAWAS AT THERL
SANGAREN, JAPUR IN PRIME MINISTER YOGAM-2015

SCALE 1:100
NORTH POINT

FOR SHOWN & REVISIONS BY: [Signature]
DATE: 12/12/2015
OWNER: [Signature]
ARCHITECT: [Signature]



SOUTH SIDE ELEVATIONS



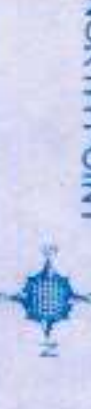
EAST SIDE ELEVATIONS

DRAWING TITLE

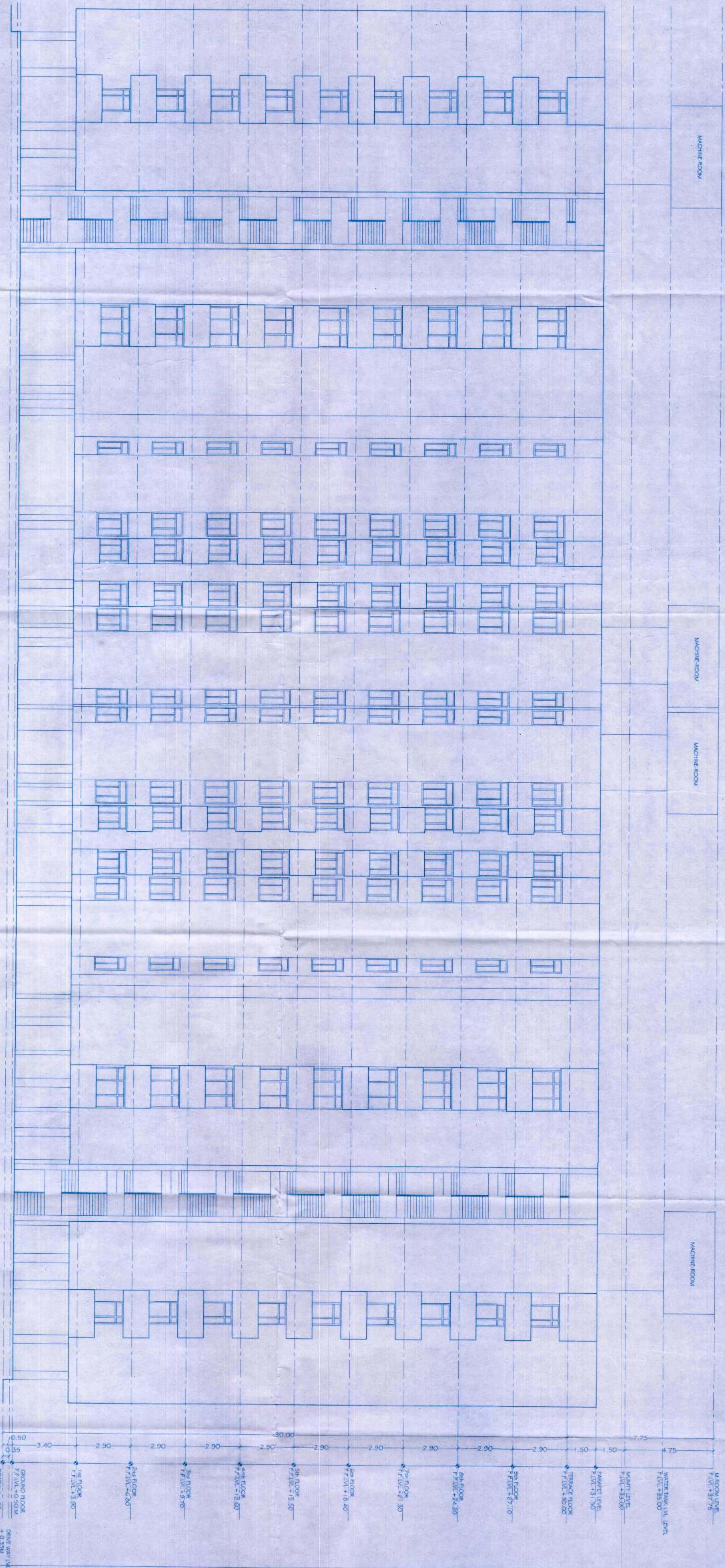
ELEVATIONS

PROJECT TITLE -
PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. GH-2 OF
SHIV VIHAR - YOLAMA AT VILLAGE - MANGANYAMA ATTENHIL
SANGNER, JALPURI IN PRIME MINISTER YOLAMA-2015

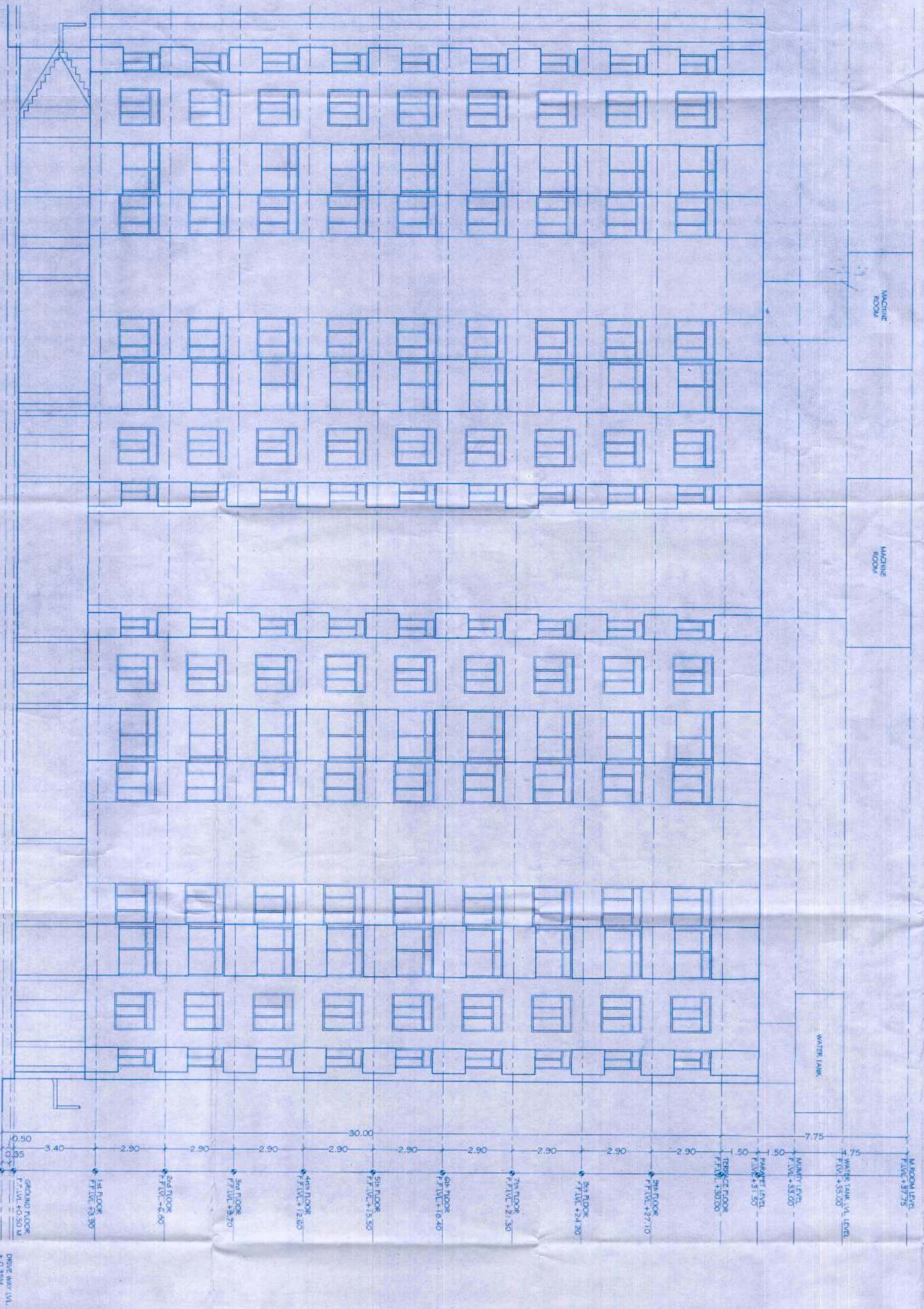
ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
104, KAMARUDDIN ROAD, JALPURI
NORTH POINT
SCALE 1:100



OWNER: **FE SHIVINI & PARELLOHNE PVT. LTD.**
ARCHITECT: **ideas**
DATE: 11/11/2015



NORTH SIDE ELEVATIONS



WEST SIDE ELEVATIONS

DRAWING TITLE

ELEVATIONS

PROJECT TITLE:
PROPOSED GROUP HOUSING AT PLOT NO. GH-4 OF
SHIV VIHAR - VADANA AT VILLAGE - MANGAYWAS AT TEHSIL
SANGNER, JALPURI IN PRIME MINISTER YOUNIA-2015

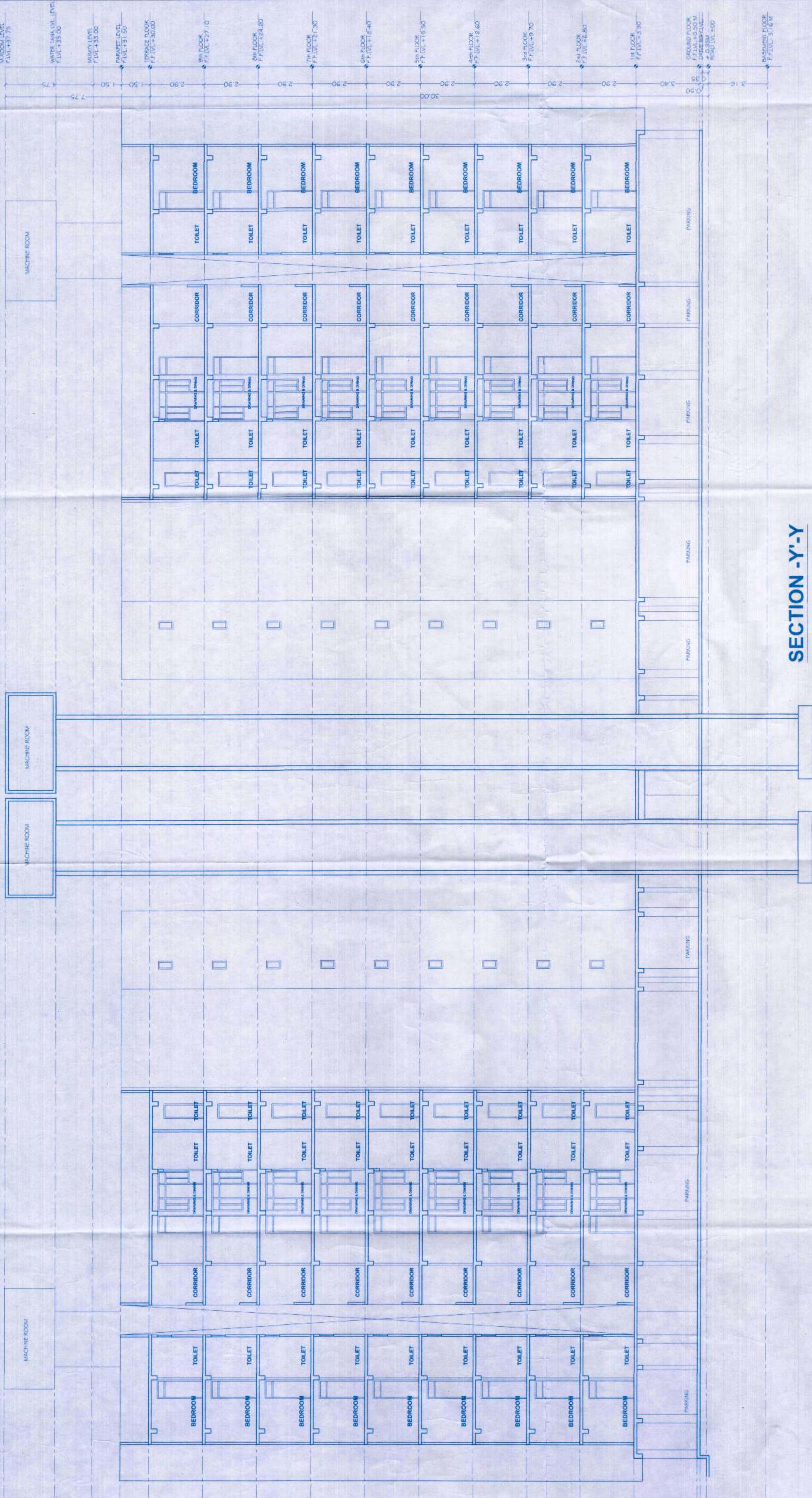


SCALE 1:100

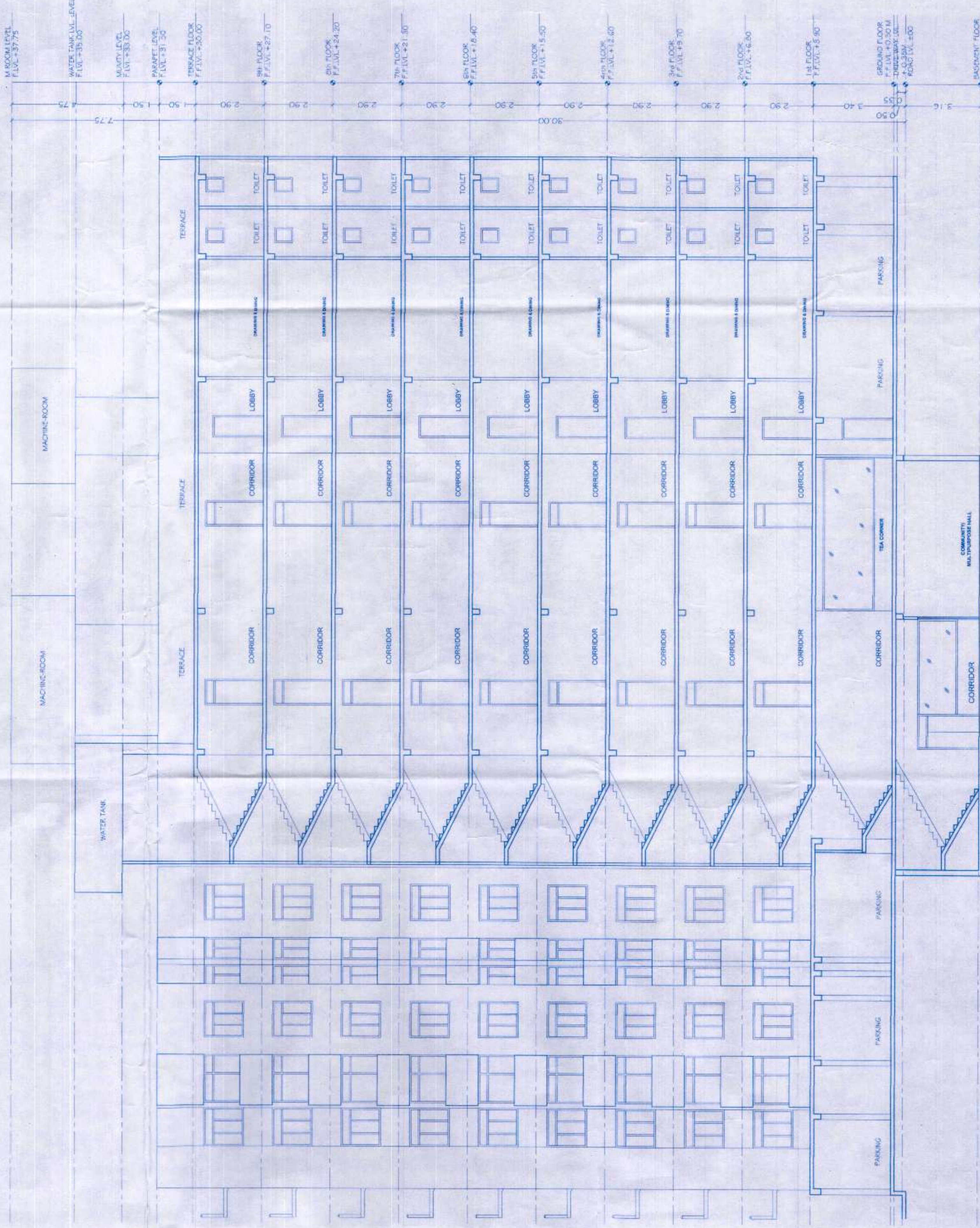
NORTH POINT



FOR SHIVILAS REALTIES PVT. LTD.
DESIGNED BY: SHIVILAS REALTIES PVT. LTD.
DRAWN BY: SHIVILAS REALTIES PVT. LTD.
CHECKED BY: SHIVILAS REALTIES PVT. LTD.
DATE: 12/12/2015
ARCHITECT



SECTION -Y'-Y



SECTION -X'-X

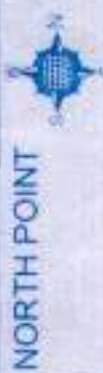
DRAWING TITLE

SECTIONS

PROJECT TITLE -
APPROVED HOUSING AT PLOT NO. 04-2 OF
SHANAR YUJANA AT VILLAGE, MANGAYANA AT TEHSIL
SANGHANER, JAIPUR IN PRIME MINISTER YUJANA-2015



SCALE 1:100



For SHANAR REAL HOME PVT. LTD.

Architect: *Signature*
BY: ANANDRA SINGH, ARCHITECT
C.A. 81712333

OWNER

ARCHITECT